मुख्यमंत्री बोले, सेमीकंडक्टर विनिर्माण बड़ा क्षेत्र, प्रदेश को आगे बढ़कर लेना होगा लाभ

सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहन के लिए नीति बनेगी: योगी

निर्देश

लखनऊ,विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार को इस संबंध में अपनी आकर्षक नीति घोषित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान इस सेक्टर में हमें इस संबंध में उत्साहजनक प्रस्ताव भी मिले हैं। हमें इन अवसरों का लाभ लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते तकनीक प्रधान युग में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्व $950 बिलियन से अधिक का है। निश्चित रूप से यह एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर में पिछले दो वर्षों से $500 बिलियन से अधिक निवेश करने की घोषणा की है। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने फैब इकाइयों के स्थापना की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन परिव्यय दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के लिए फैब इकाइयां, मिश्रित सेमीकंडक्टर, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर, असेंबली और टेस्ट इकाइयों, परीक्षण और पैकेजिंग इकाइयों का होना बेहतर इकोसिस्टम बनाता है। हमें भी ऐसा परिवेश तैयार करना होगा।

नीति में स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन वितरण का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश में तीसरा राज्य होगा। नई नीति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत छूट पर अतिरिक्त पूंजी छूट भी दिया जाना चाहिए। भूमि की खरीद-पट्टे पर स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान भी हो। इसी प्रकार, विद्युत शुल्क में छूट, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, दोहरी पावर ग्रिड नेटवर्क ट्रांसमिशन, और व्हीलिंग शुल्क, कौशल विकास और प्रशिक्षण, पेटेंट, जलापूर्ति, पॉवर बैंकिंग तथा अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए नीति में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति को तैयार करते समय इस संबंध में अन्य राज्यों की नीतियों का आंकलन भी करें। इस सेक्टर के विशेषज्ञों, स्टेक होल्डर्स से भी परामर्श करें।

शहरों में इनर रिंग रोड व कंवेंशन सेंटर बनाए जाएं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी शहरों में इनर रिंग रोड की व्यवस्था की जाए। मास्टर प्लान में इसके साथ ही मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कंवेंशन सेंटर के लिए स्थान चिह्नित किए जाएं। सभी प्राधिकरण व स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां व अवैध रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आवास पर गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन मास्टर प्लान-2031 के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया।

मल्टीलेवल पार्किंग बनाएं

उन्होंने कहा कि कपड़ा व दवा मार्केट के लिए वेयर हाउस बनाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार किसी अन्य मार्ग पर एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में प्लानिंग करते समय स्वयं के स्रोतों से आय जुटाने की व्यवस्था हो। बस स्टेशन यथासंभव शहर से बाहर स्थापित किए जाएं। मल्टीलेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास ही लॉजिस्टिक हब भी तैयार किए जाएं।